

वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल

सीएजी रिपोर्ट में राजस्व व्यय, अनुदान, उधारी और बजटीय अनुशासन में कई खामियां उजागर

नवभारत न्यूज
भोपाल, 23 जुलाई. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मध्यप्रदेश सरकार के राज्य वित्त पर अपनी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत कर दी है. रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय प्रबंधन, बजटीय अनुशासन, राजस्व व्यय, उधारी, निवेश, अनुदानों के उपयोग और सरकारी खातों के संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गंभीर टिप्पणियां की गई हैं.

उप महालेखाकार सुरेश कुमार भोपाल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में राजस्व अधिशेष तो दर्ज किया, लेकिन राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4.28 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो निर्धारित 4.12 प्रतिशत की सीमा से अधिक है. लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 2,004.48 करोड़ के राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाने से वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई. इस समायोजन के बाद राजस्व अधिशेष घटकर मात्र 431.49 करोड़ रह गया.

रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल व्यय 3,55,885.58 करोड़ रहा, जबकि कुल प्राप्त प्रावधान 4,06,734.33 करोड़ था. इसके



विधानसभा में पेश हुई नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

बावजूद 50,848.76 करोड़ की बचत हुई, जो कुल प्रावधान का लगभग 12.50 प्रतिशत है. वहीं विभागों ने 20,990.29 करोड़ की राशि समर्पित कर दी, जबकि 29,858.47 करोड़ की राशि बिना उपयोग के व्यपगत हो गई.

लेखापरीक्षा में यह भी सामने आया कि बिना पुनर्विनियोजन आदेश के 5,389.42 करोड़ का व्यय किया गया. वित्त विभाग के अंतर्गत 199.75 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भी दर्ज किया गया, जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता बताई गई है.

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान विधानसभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक बजट में से 6,253.66 करोड़ का प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ, जबकि 5,921.96 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी आवश्यकता से अधिक पाया गया. इससे बजट अनुमान तैयार

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दी गई राजस्व सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. ऊर्जा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, औद्योगिक नीति तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को दी जाने वाली सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई. सीएजी की यह रिपोर्ट राज्य के वित्तीय प्रबंधन, बजट निर्माण, व्यय नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन को लेकर कई महत्वपूर्ण संकेत देती है. रिपोर्ट में उठाए गए बिंदु विधानसभा में चर्चा के साथ-साथ शासन-प्रशासन के लिए भी सुधारात्मक कदम उठाने का आधार बन सकते हैं.

प्रमुख तथ्य
► राजकोषीय घाटा 4.28%, लक्ष्य 4.12% से अधिक .
► 2,004.48 करोड़ का राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय में दर्शाने पर आपत्ति.
► 50,848.76 करोड़ की बजटीय बचत .
► बिना बजट पुनर्विनियोजन के 5,389.42 करोड़ खर्च .
► 22,049.38 करोड़ के 19,897 उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित .
► 189 निष्क्रिय व्यतिगत जमा खातों में 206.16 करोड़ शेष .
► सरकारी निवेश पर केवल 0.52% प्रतिफल, जबकि ऋण पर औसत ब्याज 6.73% .

में प्रमुखता से उठाया गया है. 31 मार्च 2025 तक 19,897 उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे, जिनकी राशि 22,049.38 करोड़ थी. वहीं तीन वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े 189 व्यक्तिगत जमा खातों में 206.16 करोड़ शेष पाए गए.

एमपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार

17 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी

60 घंटे से जारी बारिश, वर्षा घाटा घटकर 11 प्रतिशत

भोपाल, 23 जुलाई. मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. प्रदेश में सक्रिय तीन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से पिछले करीब 60 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है.

मौसम विभाग ने शुक्रवार को 17 जिलों में भारी से अति भारी



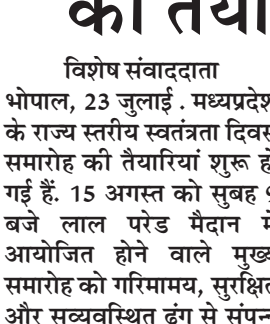
बारिश का अलर्ट जारी किया है. लगातार हो रही वर्षा से प्रदेश में मानसूनी घाटा घटकर 11 प्रतिशत रह गया है और आने वाले 24 घंटे तक कई क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है.

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर मानसून द्रोणिका, ऊपरी हवा का

स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारियां शुरू

विशेष संवाददाता
भोपाल, 23 जुलाई . मध्यप्रदेश के राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं. 15 अगस्त को सुबह 9 बजे लाल परेड मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को गरिमामय, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी व्यवस्थाएं पूरी करने पर विशेष जोर दिया गया है.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष सशस्त्र बल के निर्देश पर 24 जुलाई से लाल



चक्रवाती परिसंचरण और पूर्व-पश्चिम शिंयर जोन एक साथ सक्रिय हैं. इन तीनों मौसम प्रणालियों के कारण 20 जुलाई से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है. अर्रेंज अलर्ट वाले जिलों में आलीराजपुर, धार, बड़वानी और खरगोन शामिल हैं.

बस बैक करते समय हेलपर की पहिए के नीचे दबकर मौत

मुरैना. जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बस चालक की कथित लापरवाही के चलते बस को बैक करते समय हेलपर की पहिए के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार आज सुबह बस स्टैंड पर हेलपर संजय सिकरवार (51) बस के पीछे सफाई कर रहा था. इसी दौरान चालक ने कथित रूप से बिना ध्यान दिए बस को पीछे करना शुरू कर दिया, जिससे संजय सिकरवार बस के पहिए के नीचे आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मार्ग कायम कर बस को ज्वब कर लिया है. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है.

मनरेगा के क्रियान्वयन में कई गंभीर खामियां उजागर, सीएजी की रिपोर्ट

ग्वालियर, 23 जुलाई . भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)की मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के क्रियान्वयन ' पर तैयार रिपोर्ट क्रमांक-4 वर्ष 2026 (परफॉर्मेंस ऑडिट-सिविल) को 22 जुलाई 2026 को मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया.

संविधान के अनुच्छेद-151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत इस रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान योजना के क्रियान्वयन का व्यापक परीक्षण किया गया.

ऑडिट में योजना निर्माण, धनराशि के आवंटन एवं उपयोग, रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति, कार्यों की गुणवत्ता, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, शिकायत निवारण और पारदर्शिता की समीक्षा की गई.

ऑडिट में यह भी सामने आया कि वयनित ग्राम पंचायतों ने डेवलपमेंट प्लान तैयार नहीं किए और न ही रोजगार दिवस आयोजित किए. इसी प्रकार बहुवर्षीय जिला परिषद योजना तैयार नहीं हुई तथा जिला पंचायत स्तर पर श्रम बजट ग्राम पंचायतों की वास्तविक मांग को ध्यान में रखे बिना तैयार किए गए.

महेश प्रसाद श्रीवास्तव उप महालेखाकार प्रथम ग्वालियर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा रोजगार की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए बेसलाइन सर्वे एवं डोर-टू-डोर सर्वे नहीं कराए गए, जिससे दिव्यांगों, विधवाओं, परित्यक्तों एवं निराश्रित महिलाओं की पहचान प्रभावी ढंग से नहीं हो सकी. राज्य स्तरीय सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) योजना तैयार नहीं की गई, जबकि चयनित जनपद पंचायतों में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (BRC) भी स्थापित नहीं किए गए, जिससे क्षमता निर्माण एवं अभिसरण गतिविधियां प्रभावित हुईं.

नीट पेपर लीक पर कांग्रेस मार्च को पुलिस ने रोका

विशेष संवाददाता
भोपाल. नीट पेपर लीक प्रकरण में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा घोटालों के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तथा छात्रों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को भोपाल शहर जिला कांग्रेस कमेटेी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला. भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आगे बढ़ने से रोक दिया.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर



नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे परीक्षा घोटालों से देश के लाखों विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भविष्य संकट में पड़ गया है. प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक सहित सभी परीक्षा

अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस ने विभिन्न छात्र आंदोलनों के दौरान विद्यार्थियों पर दर्ज सभी आपराधिक प्रकरण तत्काल वापस लेने तथा संसद में छात्रों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े

अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान

विशेष संवाददाता
भोपाल, 23 जुलाई . मध्यप्रदेश जेल विभाग के जेल मुख्यालय, भोपाल में पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्मान में गरिमामय पिपिंग समारोह आयोजित किया. समारोह में पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नई जिम्मेदारियों के लिए सम्मानित करते हुए उनके उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और सेवा भावना की सराहना की गई.

जेल विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश चंद गुप्ता तथा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं डॉ. वरुण कपूर ने भोपाल केंद्रीय जेल और जेल मुख्यालय के पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वर्दी पर स्टार एवं लाल निशान लगाकर उन्हें सम्मानित किया.



सिविल संवर्ग के पदोन्नत कर्मचारियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया. समारोह में हुए बताया कि जेलों की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, बर्दियों के लिए अतिरिक्त आवासीय क्षमता, बेहतर कैंटीन सुविधाएं, आरओ पेयजल प्रणाली, बर्दियों के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए योग शिविर, जेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए ओपन जिम तथा गप आवासों का निर्माण कराया गया है.

वरुण कपूर ने अपने लगभग दस माह के कार्यकाल में जेल विभाग में किए गए सुधारों की जानकारी देते हुए बताया कि जेलों की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग, बर्दियों के लिए अतिरिक्त आवासीय क्षमता, बेहतर कैंटीन सुविधाएं, आरओ पेयजल प्रणाली, बर्दियों के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए योग शिविर, जेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए ओपन जिम तथा गप आवासों का निर्माण कराया गया है.

एसीई की बेनामी संपत्ति जांच में 17 करोड़ का आंकड़ा पार

- लोकायुक्त ने खंगाले 25 बैंक खाते
- फर्माओं के खातों में मिले 62 लाख रुपए

नव भारत न्यूज
इंदौर, 23 जुलाई. एडिशनल चीफ इंजीनियर (एसीई) शिवराम सेमिल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त की जांच आगे बढ़ने के साथ संपत्तियों का आंकड़ा बढ़कर 17.12 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है.

पहले चरण की कार्रवाइ में सामने आई संपत्तियों के बाद अब जांच एजेंसी ने बैंक खातों, एफडी, निवेश और मुरैना स्थित संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है. लोकायुक्त पुलिस की जांच में सेमिल, उनके परिवार और उनसे जुड़ी फर्माओं के नाम से संचालित 25 बैंक खातों की जानकारी सामने आई है. इनमें एसबीआई और आईडीबीआई बैंक के खाते शामिल हैं. जांच में सामने आया है कि ये खाते शिवराम सेमिल, सामने आई संपत्तियों के बाद अब जांच एजेंसी ने बैंक खातों, एफडी, निवेश और मुरैना स्थित संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है. लोकायुक्त पुलिस की जांच में सेमिल, उनके परिवार और उनसे जुड़ी फर्माओं के नाम से संचालित 25 बैंक खातों की जानकारी सामने आई है. इनमें एसबीआई और आईडीबीआई बैंक के खाते शामिल हैं. जांच में सामने आया है कि ये खाते शिवराम सेमिल,

उनकी पत्नी रामबेटी, बेटे सौरभ, बहु सुनीता और संबंधित फर्मों के नाम पर संचालित थे.

जांच में मुरैना स्थित संपत्तियां भी सामने आई हैं. यहां करीब 50 लाख रुपए कीमत का मकान मिला है, जिसमें रखे घरेलू सामान का मूल्यंकन करीब 7.51 लाख रुपए किया है. इसके अलावा 20 बाय 40 फीट का प्लॉट और करीब सवा बीघा कृषि भूमि होने की जानकारी मिली है. इन संपत्तियों के दस्तावेजों का सत्यापन पंजीयन विभाग से कराया जा रहा है. लोकायुक्त सूत्रों ने यह भी बताया कि सेमिल, उनके परिवार और संबंधित फर्मों के बैंक खातों को फ्रीज करा दिया है. आयकर विभाग से परिवार के सदस्यों के रिटर्न की जानकारी मांगी गई है. शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश की जानकारी के लिए सेबी को भी पत्र भेजा है. लोकायुक्त अधिकारी का कहना है कि जांच अभी जारी है, दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच पूरी होने के बाद संपत्ति के अंतिम मूल्यांकन और आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी.

पेज एक का शेष

यूसीसी को मिला व्यापक जन समर्थन : डॉ . मोहन यादव
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे यात्रा समय कम होगा, ईंधन की बचत होगी और जाम से राहत मिलेगी। दूसरी लेन का निर्माण भी अंतिम चरण में है। इस अवसर पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका त्याग, साहस और बलिदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश समान अवसर और समान कानून के उस संकल्प को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है .जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था।